सम्बन्ध में विशिष्ट प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था । 1983–84 में राज्य सरकार ने निम्नलिखित तीन निर्माण-कार्यों के प्रस्ताव भेजे थे जिन्हें भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया गया था :–

(लाख रुपये में)

निर्माण कार्यों का नाम	स्वीकृत लागत
1. अचंकमार-किओंची सड़क	192.27
2. मदवास-कुशमी मार्ग पर 6 पुल और पहुंच सड़कें	170.04
3. मदवास-कुशमी-रुण्डा-भदुरा सड़क	46.35

आदिवासी गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़े जाने की योजना

@3292. **श्री अजीत जोगी :**
श्री बेकल "उत्साही" :
श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आदिवासी क्षेत्रों के 500 लोगों से ज्यादा आबादी वाले गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो आदिवासी क्षेत्रों के कम आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की केन्द्रीय सरकार की क्या योजना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की केन्द्रीय योजना को 1987–88 से बन्द कर दिया गया था।

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 2580, 16 दिसम्बर, 1991 से स्थानान्तरित ।

Farmers below poverty-line in Arunachal Pradesh

@@3293. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the present number of small and marginal farmers living below the poverty-line in Arunachal Pradesh;

(b) whether Government propose to launch any schemes to improve their living conditions; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) There are 16,267 small farmers and 12,765 marginal farmers living below poverty line in Arunachal Pradesh.

(b) and (c) The following schemes are already being implemented by Government for development of small and marginal farmers—

(i) Integrated Rural Development Programme (IRDP).

(ii) Assistance to Smalj and Marginal Farmers for increasing agricultural production through construction of shallow tube-wells and dug wells on the holdings of small and marginal farmers in the State selected for Special Foodgrain Production Programme (SFPP).

(iii) Establishment of Farmers' Agro-Service Centre and Introduction nad Adoption of Seeding and Planting machines.

(iv) Lab-to Land Programme.

(v) Special Livestock Breeding Programme.

(vi) Integrated Programme for Rice Development.

@@Previously Unstarred Question 2258 transferred from the 13th Dec. 1991.